साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 170 | जौनपुर, शनिवार, 16 मार्च 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने राष्ट्रपति भवन परिसर में अपने नाम पर बनी सड़क का उद्घाटन किया

नई दिल्ली, एजेंसी। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भवन एस्टेट में उनके नाम पर एक सड़क का उद्घाटन किया। सुबह में, एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिति के कुछ सदस्यों के साथ कोविंद ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के समर्थन में समिति की रिपोर्ट सौंपने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। कोविंद ने सोशल मीडिया पर इसके लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "आज राष्ट्रपति भवन में मेरे नाम पर बनी सड़क यानी 'वीथि' के उद्घाटन पर सम्मानित महसूस किया। हमारी विरासत को संरक्षित करने का यह महत्वपूर्ण कार्य समावेशिता और सांस्कृतिक गौरव के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस भाव के लिए आभारी हूं।" उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति भवन संग्रहालय में उनकी और उनकी पत्नी सविता कोविंद की तस्वीर और यादगार वस्तुओं का अनावरण करने वाले मुर्मू के 'सहृदय' भाव से वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, "हमारी विरासत को संजोया और मनाया जाता देखना सम्मान की बात है। मैं इसमें शामिल सभी लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं।

निर्वाचन आयुक्तों को चुनने की नयी प्रणाली से पता चलता है कि अंतिम फैसला पीएम का – शरद

मुंबई, एजेंसी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद गुट) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि निर्वाचन आयुक्तों को चुनने की नयी प्रणाली से पता चलता है कि उनके चयन पर अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का होता है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने नये निर्वाचन आयुक्त के रूप में बृहस्पतिवार को पूर्व नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार के नाम की सिफारिश की। चयन समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें सरकार द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता सदस्य होते हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पवार ने कहा, इससे पहले, दो केंद्रीय मंत्रियों के साथ उच्चतम न्यायालय के एक न्यायमूर्ति भी निर्वाचन आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया का हिस्सा थे।

हालांकि, हाल ही में चयन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए और उन्होंने शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति को इस प्रक्रिया से हटा दिया।'' उन्होंने कहा, '' नयी प्रणाली के अनुसार दो (केंद्रीय) मंत्रियों और विपक्ष के नेता को निर्वाचन आयुक्तों का चयन करने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब हैकि केवल उन्हीं (उम्मीदवारों) को नियुक्त किया जाएगा जिसे मोदी जी तय करेंगे।

नए निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश और सुखबीर ने प्रभार संभाला

नयी दिल्ली, एजेसी। नव नियुक्त निर्वाचन आयुक्तों.. ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने शुक्रवार को अपना प्रभार संभाल लिया। दोनों पूर्व नौकरशाहों को बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।

वे मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में हाल में एक नया कानून लागू होने के बाद, निर्वाचन आयोग में नियुक्त किए गए पहले सदस्य हैं। एक प्रवक्ता ने बताया कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने ऐसे ऐतिहासिक समय पर उनकी नियुक्ति के महत्व के बारे में बात की जब निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव कराने की तैयारियां कर रहा है। अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और आठ मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में ये पद खाली हो गए थे। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों वर्ष 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर से और सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर से आते हैं।

अब यूपी फार्मा सेक्टर का उत्पादक और निर्यातक बन जाएगा - सीएम योगी

गोरखपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फार्मा सेक्टर में उत्तर प्रदेश का पहले कंज्यूमर (उपभोक्ता) स्टेट था। दवाएं व अन्य जरूरी मेडिकल उत्पाद बाहर से आते थे। अब यूपी फार्मा सेक्टर का उत्पादक और निर्यातक बन जाएगा। इसके लिए सरकार ललितपुर में 2000 एकड़ में फार्मा पार्क बना रही है। यूपी में मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है। इससे फार्मेसी के क्षेत्र में युवाओं को भी व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे। सीएम योगी शुक्रवार को मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) में 24.69 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली फार्मेसी बिल्डिंग के शिलान्यास एवं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 4000 विद्यार्थियों के टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 15 विद्यार्थियों को अपने हाथों से टैबलेट और स्मार्टफोन दिया। सीएम योगी ने कहा कि आज से सात साल पहले भी यूपी में सब कुछ था लेकिन आगे बढ़ने के संकल्प का अभाव था। प्रदेश वही है, लोग वही हैं, मशीनरी भी वही है लेकिन कार्य संस्कृति बदली तो परिणाम सबके सामने है। आज उत्तर प्रदेश नया और बदला हुआ प्रदेश नजर आता है। यह प्रगति और निवेश का प्रदेश बन गया है। यहां हरेक सेक्टर में पर्याप्त अवसर और आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। युवाओं को प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। यह शब्द उनके लिए है जिन्हें कुछ नहीं करना है। जिनके पास सामर्थ्य, विश्वास और साहस है उनके लिए सबकुछ संभव है। सीएम ने कहा कि जहां चुनौतियां होंगी, वहीं संभावनाएं भी होती हैं। संभावनाओं और अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना से स्मार्टफोन और टैबलेट से आच्छादित कर यूपी के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में दो करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। स्मार्टफोन और टैबलेट में केंद्र और राज्य सरकार की उन योजनाओं को भी जोड़ा गया है जो युवाओं के भविष्य और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक हैं।

तकनीकी रूप से सक्षम होकर युवा आगे बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देंगे। विकसित भारत बनाने में तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। आजादी के नायकों में शामिल और बीएचयू के संस्थापक मदन मोहन मालवीय को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मालवीय जी के नाम पर बना एमएमएमयूटी लगातार उपलब्धियों के पथ पर बढ़ रहा है।

दक्षिण में बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी के अभियान को धार दे रहे हैं पीएम मोदी

नयी दिल्ली, एजेंसी। तीन राज्यों में राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले शुक्रवार को दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी। भाजपा की कोशिश दक्षिण क्षेत्र के पांच राज्यों से अधिक से अधिक सीट हासिल कर उस मिथक को तोड़ने की है कि उसका दबदबा सिर्फ हिंदी पट्टी के ही क्षेत्रों में है। भाजपा नेताओं ने कहा कि मोदी अगले चार दिनों यानी 19 मार्च तक सभी दक्षिणी राज्यों का दौरा करेंगे और उन स्थानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 17 मार्च को आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) –भाजपा–जन सेना की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। यहां की सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी को टक्कर देने के लिए हाल में तीनों दलों ने हाथ मिलाया है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की रैली को तीन दलों के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री शनिवार को तेलंगाना के नगरकुरनूल और कर्नाटक के गुलबर्गा में प्रचार करेंगे। गुलबर्गा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का गढ़ रहा है। हालांकि, 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने भाजपा प्रतिद्वंद्वी से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि वह 18 मार्च को तेलंगाना के जगतियाल और कर्नाटक के शिमोगा में रैलियों को संबोधित कर सकते हैं और तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक रोड शो का नेतृत्व करेंगे। वह केरल के पलक्कड़ में एक रोड शो करेंगे और 19 मार्च को तमिलनाडु के सलेम में एक रैली को संबोधित करेंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों में तमिलनाडु और केरल में रैलियां और तेलंगाना में रोड शो शामिल हैं। पांच राज्यों के अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में लोकसभा की एक सीट है। दक्षिण भारत में 131 सीट हैं। भाजपा 2011 में पुडुचेरी के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी।

चुनावी बाण्ड खुलासे से बीजेपी की लूट देश के सामने आई – गहलोत

जयपुर, एजेंसी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावी बॉण्ड को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आंकड़े सामने आने से उसकी लूट देश के सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सट्टेबाजी, जुआ आदि का काम करने वाली कंपनियों तक से चंदा लिया है और यही भाजपा के चरित्र का सत्यापन है। गहलोत की यह टिप्पणी निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी बॉण्ड के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के एक दिन बाद आई है। गहलोत ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी बयान में कहा, ''इलेक्टोरल बॉण्ड का डाटा सार्वजनिक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा मचाई गई लूट देश के सामने आ गई है।'' उन्होंने लिखा, ''चुनावी बॉन्ड की जानकारी से तो ऐसा लगता है कि ईडी, भाजपा का वसूली विभाग बनकर रह गई है। जिन कंपनियों पर केंद्रीय एजेंसियों ने छापे मारे, उन्होंने ही भाजपा को इलेक्टोरल बॉण्ड से चंदा दिया और उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई रुक गई। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार, ''भाजपा ने सट्टेबाजी, जुआ आदि का काम करने वाली कंपनियों तक से चंदा लिया और यही भाजपा के चरित्र का सत्यापन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से कह रही थी कि इलेक्टोरल बॉण्ड देश का सबसे बड़ा घोटाला है। उन्होंने कहा ''अब यह देश के सामने आ गया है कि भाजपा देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार का सरकारीकरण कर दिया है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं वह भी करोड़ों रुपये का चंदा भाजपा को दे रही हैं।

रिश्वतखोरी को वैध बनाने की योजना थी चुनावी बाण्ड – चिदंबरम

नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि चुनावी बॉण्ड योजना को 'रिश्वतखोरी को वैध बनाने' और सत्तारूढ़ पार्टी को इसका सबसे बड़ा लाभार्थी बनाने के मकसद से तैयार किया गया था। चुनावी बॉण्ड के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद चिदंबरम ने यह टिप्पणी की है। उन्होंने 'इंडिया टुडे कॉन्क्लेव–2024' में कहा, ''जिस दिन चुनावी बॉण्ड योजना सामने लाई गई थी, उसी दिन मैंने कहा था कि यह वैध रिश्वतखोरी है। मैं अब भी उस पर कायम हूं। बेहतर प्रणाली एक बहु–आयामी प्रणाली होती है। चिदंबरम ने कहा, ''चुनाव लोकतंत्र का पर्व है। इसमें बहुत सारी बयानबाजी, गीत–नृत्य, भाषण होने चाहिए... चुनाव आयोग ने सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया है... उम्मीदवारों के लिए खर्च की बड़ी सीमा की अनुमति दें। इतनी कम रकम पर कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता और जीत नहीं सकता।'' कांग्रेस नेता ने कहा कि बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाने के बजाय चुनावी बॉण्ड योजना पेश की गई, जो ''रिश्वतखोरी को वैध बनाने'' और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी कि सत्तारूढ़ दल इसका सबसे बड़ा लाभार्थी बने। यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करना बहुत आसान है, तो चिदंबरम ने कहा, ''कुछ भी अवश्यंभावी नहीं है। जब 2004 में पूरे देश में 'इंडिया शाइनिंग' (भारत उदय) अभियान जोरों पर था, तो आपका चौनल कहां था? श्री (अटल बिहारी) वाजपेयी, जो एक उदारवादी व्यक्ति थे, उन्होंने अभियान का नेतृत्व किया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें आठ सीट के अंतर से मात दे दी थी।'' उनका कहना था, ''मैं मानता हूं कि अगर हिंदी भाषी राज्य उसी तरीके से वोट करते हैं, जैसे उन्होंने पिछली बार वोट दिया था, तो हमारे सामने एक लड़ाई है। 'इंडिया' गठबंधन इस लड़ाई से कैसे निपटेगा, यह उसके नेताओं को तय करना है। हम तमिलनाडु में 2019 का परिणाम दोहराएंगे।

दिल्ली की अदालत ने खारिज की केजरीवाल की समन पर रोक लगाने वाली याचिका, कहा-ट्रायल कोर्ट में दें आवेदन

नई दिल्ली, एजेंसी। राउज एवेन्यू कोर्ट की सत्र अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर शिकायतों के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी है। सेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के वकीलों से कहा कि पेशी से छूट के लिए आप ट्रायल कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। केजरीवाल ने उन्हें जारी समन से बचने के लिए ईडी द्वारा दायर दो शिकायतों पर संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्पाद शुल्क नीति मामले में जमानत देने से इनकार करने के शीर्ष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी सुधारात्मक याचिका खारिज करने के बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की अनुमति दी। मामले को 18 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली चार–न्यायाधीशों की पीठ ने पूर्व डिप्टी सीएम की सुधारात्मक याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उपचारात्मक याचिकाओं को खुली अदालत में सूचीबद्ध करने का आवेदन खारिज किया जाता है। हमने उपचारात्मक याचिकाओं और संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया है। हमारी राय में, रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा मामले में इस न्यायालय के फैसले में बताए गए मापदंडों के भीतर कोई मामला नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 को यह कहते हुए सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि सामग्री और सबूत हैं जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके खिलाफ आरोपों में से एक का अस्थायी रूप से समर्थन करते हैं – कि 14 थोक शराब वितरक लगभग 10 महीनों में 338 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ कमाया, जब अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति लागू थी।

नीतीश 9.0 में स्पेशल 21 की एंट्री, बीजेपी से 12, जेडीयू से 9 मंत्रियों ने ली शपथ

बिहार, एजेंसी। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ गठबंधन टूटने के कुछ हफ्ते बाद, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल का विस्तार 15 मार्च को हो गया। नए मंत्रियों के शुक्रवार की शाम 6:30 बजे पद की शपथ ली। नीतीश कुमार की कैबिनेट में 21 मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी से 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं जेडीयू के कोटे से 9 मंत्री बनाए गए। यह घटनाक्रम भाजपा और जदयू नेताओं के बीच एक बैठक के बाद कई सप्ताह तक चली अटकलों के बाद आया है। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और विजय सिन्हा शामिल हुए, साथ ही जेडीयू नेता ललित सिंह, संजय झा, बिजेंद्र यादव और विजय चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। बिहार के

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी को राज्य की मंत्री के तौर पर शपथ दिलायी। बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी बेतिया विधानसभा क्षेत्र से आती हैं। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंत्री पद की शपथ ली। वो तीन बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं। बिहार के राजभवन में शुक्रवार शाम एक समारोह के दौरान भाजपा नेता नीरज कुमार सिंह ने राज्य के मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी ने बिहार के मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। जनता दल यूनाइटेट की वरिष्ठ नेता लेसी सिंह ने बिहार की मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। जदयू के वरिष्ठ नेता ने बिहार के मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता नीतीश मिश्रा ने मैथिली में बिहार के मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने बिहार के मंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। वर्तमान में मंत्रिपरिषद, जिसमें 30 से अधिक सदस्य हो सकते हैं।

चुनाव 2024 के लिए आचार संहिता लगने से पहले कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का ऐलान

मध्य प्रदेश, एजेंसी। देश भर में शनिवार 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगाई जाएगी। इससे पहले ही मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता चार प्रतिशत तक बढ़ाया है। मध्य प्रदेश में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब उन्हें 46% की दर से भुगतान किया जाएगा। अब तक कर्मचारियों को 42: महंगाई भत्ता दिया जाता था। बता दें कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक मार्च से लागू होगा। इसका भुगतान कर्मचारियों को अप्रैल महीने के वेतन में ही किया जाएगा। लंबे समय से राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। महंगाई भत्ता ना बढ़ने को लेकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी भी थी। वहीं राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अभी महंगाई भत्ता बढ़ने के लिए इंतजार करना होगा। राज्य में साढ़े चार लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जो महंगाई भत्ता बढ़ने की आस लगाए बैठे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 38: महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाता है। वहीं कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्मचारियों को बधाई भी दी है।

संपादकीय

अधिनायकवाद और स्वतंत्रता की दुनिया

हाल ही में ध्रुव राठी नाम के एक युवक का एक लोकप्रिय वीडियो आया था, जिससे सरकार के समर्थक नाराज हो गए। इसके व्यापक तर्क को शीर्षक से समझा जा सकता है, जो था ष्क्या भारत तानाशाही बन रहा है?ष वीडियो में इस्तेमाल किए गए उदाहरणों में भाजपा द्वारा हाल ही में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए पैनल में धांधली, विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग आदि शामिल हैं। शब्दकोश में तानाशाही को ष्सरकार का एक रूप जिसमें एक व्यक्ति या एक छोटे समूह के पास प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति होती हैष और ष्सरकार का एक रूप जिसमें पूर्ण शक्ति एक व्यक्ति या एक छोटे समूह में केंद्रित होती हैष के रूप में परिभाषित किया गया है। मैं इसे पाठकों पर छोड़ दूँगा कि क्या ये परिभाषाएँ आज भारत में हमारे चारों ओर जो हो रहा है उससे मेल खाती हैं। |कअमतजपेमउमदज ष्तानाशाहष शब्द, ष्फासीवादीष शब्द की तरह, अत्यधिक उपयोग किया जाता है और इसका वास्तविक अर्थ खो सकता है क्योंकि इसे परिभाषा के बजाय दुरुपयोग के शब्द के रूप में देखा जाता है। जब सामाजिक वैज्ञानिक आशीष नंदी ने मुख्यमंत्री बनने से पहले हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री से मुलाकात का वर्णन किया, तो उन्होंने निम्नलिखित लिखारू "यह एक लंबा, मनोरंजक साक्षात्कार था, लेकिन इससे मुझे कोई संदेह नहीं हुआ कि यह एक फासीवादी का एक क्लासिक, नैदानिक मामला था। मैं कभी भी श्फासीवादीश शब्द का प्रयोग दुर्व्यवहार के रूप में नहीं करताय मेरे लिए यह एक निदान श्रेणी है जिसमें न केवल किसी की वैचारिक स्थिति बल्कि विचारधारा को प्रासंगिक बनाने वाले व्यक्तित्व लक्षण और प्रेरक पैटर्न भी शामिल हैं। नंदी ने कहारू "मोदी, मुझे पाठकों को यह बताते हुए कोई खुशी नहीं हो रही है कि मोदी वस्तुतः उन सभी मानदंडों पर खरे उतरे हैं जो मनोचिकित्सकों, मनोविश्लेषकों और मनोवैज्ञानिकों ने सत्तावादी व्यक्तित्व पर वर्षों के अनुभवजन्य काम के बाद स्थापित किए थे। उनमें शुद्धतावादी कठोरता, भावनात्मक जीवन की संकीर्णता, प्रक्षेपण के अहंकार की रक्षा का व्यापक उपयोग, इनकार और हिंसा की कल्पनाओं के साथ अपने स्वयं के जुनून का डर का समान मिश्रण था – सभी स्पष्ट पागल और जुनूनी व्यक्तित्व लक्षणों के मैट्रिक्स के भीतर सेट थे। मुझे अब भी वह शांत, नपा–तुला लहजा याद है जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ लौकिक साजिश के सिद्धांत को विस्तार से बताया था, जिसने हर मुसलमान को एक संदिग्ध गद्दार और संभावित आतंकवादी के रूप में चित्रित किया था। मैं साक्षात्कार से स्तब्ध होकर बाहर आया३" तानाशाही की ओर लौटने के लिए, मेरे विचार से एक कम भावनात्मक और अधिक विश्वसनीय प्रश्न यह पूछना है कि क्या हम सत्तावादी शासन के अधीन हैं। इसे ष्दूसरों की इच्छाओं या राय के प्रति चिंता की कमीष के रूप में परिभाषित किया गया है। अब, आइए यह देखने के लिए कुछ संकेतक देखें कि क्या यह मामला है। क्या रहे हैं? पहला, क्या सरकार के अंदर के लोगों की इच्छाओं और राय की कोई चिंता है? इसका उत्तर देने के लिए, आइए दो महत्वपूर्ण मामलों पर नजर डालें जहां हमारे पास निर्णायक सबूत हैं। पहला 24 मार्च, 2020 का राष्ट्रीय लॉकडाउन है। बीबीसी ने लॉकडाउन के एक साल बाद 240 आरटीआई (सूचना का अधिकार अनुरोध) दायर की, यह पूछने के लिए कि मोदी सरकार में कौन जानता था कि उस शाम लॉकडाउन की घोषणा की जा रही थी। क्या आपदा प्रबंधन से परामर्श लिया गया? या वित्त मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय? सरकार की ओर से उत्तर थारू ष्नहींष। किसी से परामर्श या सूचना नहीं दी गई। दूसरा है नोटबंदी. 8 नवंबर, 2016 को कैबिनेट को बुलाया गया और मंत्रियों को अपने मोबाइल फोन नहीं लाने के लिए कहा गया, जिसका मतलब है कि उन्हें तब तक पता नहीं था जब तक कि पीएम ने उन्हें नहीं बताया कि उस शाम के बाद 1,000 रुपये और 500 रुपये के नोट बेकार हो जाएंगे। चूँकि मंत्रियों को पता नहीं था, मंत्रालयों को पता नहीं था और उन्होंने इनमें से किसी भी घटना के लिए तैयारी नहीं की। सरकार के संसदीय स्वरूप सामूहिक जिम्मेदारी नामक चीज पर कार्य करते हैं। लेकिन नये भारत में नहीं. भारत में, राज्य के प्रमुख को नई संसद के उद्घाटन में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि प्रधान मंत्री अध्यक्षता करना चाहते हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार राज्य का प्रमुख अनुपस्थित होना चाहिए। इसी तरह, और इसी कारण से, राज्य के प्रमुख को उस मंदिर के उद्घाटन में आने के लिए नहीं कहा जाता है जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री करना चाहते हैं। इस पर सवाल नहीं उठाया जाता, विरोध तो बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि यह विचार कि केवल एक व्यक्ति ही राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, यहां स्वीकार कर लिया गया है। हर जगह उसकी तस्वीर देखिएय कोई इससे बच नहीं सकता. प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो का दुरुपयोग करके इस सरकार ने विपक्ष के साथ क्या किया है और क्या कर रही है, इस पर हमें ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। उस पर रोजाना अपडेट होता है. यह कोई मामला नहीं है कि संवैधानिक विपक्ष की ष्इच्छाओं और रायष के लिए कोई चिंता है। नागरिक समाज में जो लोग असहमत हैं, उन्होंने यह भी देखा है।

भारत को एक एशियाई केंद्र के रूप में फिर से कल्पना करने

आदित्य

भारतीय उपमहाद्वीप का यह नाम एक कारण से रखा गया है। भारत का विशाल, हीरे के आकार का भूभाग पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया के बीच में स्थित है। इसका दक्षिणी प्रायद्वीप हिंद महासागर में काफी फैला हुआ है, और उत्तर में मध्य एशिया के संसाधन–संपन्न लेकिन भूमि से घिरे देश स्थित हैं। एशिया के शाब्दिक चौराहे पर यह भौगोलिक स्थिति भारत को एशियाई सदी के निर्माण में एक संभावित धुरी बनाती है। एक ऐसी सदी जिसमें पश्चिम एशिया के ऊर्जा आपूर्तिकर्ता पूर्वी एशिया के ऊर्जा उपभोक्ताओं को भोजन देते हैं और मध्य एशिया के संसाधन संपन्न लेकिन भूमि से घिरे देशों को भारत के हिंद महासागर में मौजूद दर्जनों बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात बाजार मिलते हैं। इसके अलावा, भारत पश्चिम से पूर्व और वीजा–विपरीत चलने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण समुद्री वाणिज्य मार्गों (एसएलओसी) पर सवार है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का अंतिम छोर, इंदिरा पॉइंट, मलक्का जलडमरूमध्य से मात्र 675 किलोमीटर दूर है, जो छह–डिग्री चौनल पर हावी है। |कअमतजपेमउमदज हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में चीन के सबसे महत्वपूर्ण एसएलओसी भी शामिल हैं। चीन का 75 प्रतिशत तेल आयात मध्य पूर्व और अफ्रीका से होता है। चीन प्रतिदिन 11.28 मिलियन बैरल से अधिक का आयात करता है। भारत, चीन, रूस, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच परस्पर क्रिया एशियाई शक्ति की गतिशीलता का आर्थिक आधार बनती है। निस्संदेह, एशिया में अन्य उभरती हुई शक्तियां हैं जिन्होंने अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाए हैं। एशिया इस सदी में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रही है, और आने वाले दशकों तक भी यही स्थिति बनी रहेगी। एशियाई देशों के बीच व्यापार पिछले तिमाही शताब्दी में हर साल विश्व व्यापार की तुलना में तेजी से बढ़ा है, जो आंशिक रूप से चीन की आक्रामक वृद्धि और आंशिक रूप से पूर्वी एशिया द्वारा अपने बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोड़ने से प्रेरित है। लेकिन कहानी में एक बड़ा हिस्सा गायब हैरू अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए, एक एशियाई सदी को भारत को

एक संयोजक के रूप में, माल के एक प्रोसेसर के रूप में, जिसकी एशिया को आवश्यकता है, परिवहन और रसद, कुशल व्यापारिक बाजारों जैसी सेवाओं के प्रदाता के रूप में आवश्यकता होती है। एक्सचेंज, और वित्तीय सेवाएँ जो व्यापार को रेखांकित करती हैं, जैसे क्रेडिट और बीमा, और एशियाई देशों के उत्पादों के लिए एक महाद्वीप के आकार के उपभोक्ता बाजार के रूप में। यह संबंध गायब हुआ हिस्सा है जो तेजी से भारत के विकास को शक्ति प्रदान कर सकता है, बशर्ते वह पाकिस्तान के इतिहास के बोझ को त्यागने में सक्षम हो और अस्थिर सीमा प्रश्न पर चीन के साथ एक रास्ता तलाशने में सक्षम हो, जो अपनी नवीनतम अभिव्यक्ति में इन दोनों के बीच संबंधों को खराब कर रहा है। अब पिछले चार वर्षों में देश। भारत की एशियाई क्षमता को साकार करने के लिए क्या आवश्यक है? भारत को अपने पड़ोसियों को खतरों के बजाय अवसरों के रूप में देखना शुरू करने के लिए मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता होगी। विश्वास की एक ऐसी छलांग जिसे बनाना जितना आसान है, कहना उतना आसान नहीं। इसके लिए एशियाई और हिंद महासागर के देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग की आवश्यकता होगी। भविष्य की एशियाई अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बुनियादी ढाँचा शामिल है जो एशिया को भारत के माध्यम से जोड़ेगा, नियामक ढाँचे, और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और सीमा समझौते जो आर्थिक क्षमता को शांतिपूर्ण ढंग से साकार करने की अनुमति देंगे। यह भारत के वर्तमान जोर से एक बड़ा बदलाव होगा। वर्तमान में, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप इसके निर्यात के लिए भारत के सबसे बड़े और दूसरे सबसे बड़े बाजार हैं। भारत के व्यापार में एशियाई देशों की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में उन देशों की आर्थिक वृद्धि के साथ बढ़ी है, लेकिन एशिया के केंद्र में भारत की क्षमता को पूरी तरह से साकार करने के लिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं और एक व्यवस्थित प्रयास की आवश्यकता है। भारत द्वारा आरसीईपी से बाहर निकलने के बाद, पूर्वी एशिया में कई प्रमुख आवाजों ने निराशा व्यक्त की, लेकिन यह भी तर्क दिया कि एशियाई सदी भारत के साथ या उसके बिना, किसी न किसी रूप में आगे बढ़ेगी। लेकिन भारत के बिना एशिया पूर्वी एशिया और पश्चिम एशिया, मध्य एशिया और हिंद महासागर एशिया में विभाजित है। भारत इन सभी को एक साथ लाता है और इसमें भारत की प्रतिभा निहित है। हिंद महासागर पर 28 देशों की तटरेखा है। साथ में, उनकी जीडीपी है लगभग +11 ट्रिलियन, और जनसंख्या लगभग 2.8 बिलियन। इनमें मध्य एशिया के छह भूमि–बद्ध देशों को जोड़ें, जो एक विशाल संसाधन–संपन्न क्षेत्र को कवर करते हैं और कम आबादी वाले हैं, और मंगोलिया, रूस के साइबेरिया, साथ ही चीन को हिंद महासागर और अरब सागर के माध्यम से ऊर्जा और संसाधन मार्ग होने से लाभ होगा। . हिमालय एक दुर्गम वातावरण है जहां बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने की तकनीक, जिसमें सुरंगों की बोरिंग भी शामिल है, अब काफी अच्छी तरह से विकसित हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले, कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए एशिया को शांति सुनिश्चित करनी होगी। महान शक्ति प्रतिद्वंद्विता के वर्तमान भू–राजनीतिक माहौल में, यह तेजी से चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। लेकिन ऐसे ठोस कदम हैं जो भारत उठा सकता है। पहला है इसकी विवादित सीमाओं का निपटारा करना ताकि इसे इसके उत्तर से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव किया जा सके।

भारत के विकास पर मोदी की गारंटी दिमाग चकराने वाली हो सकती

आदित्य

जब 2014 के बाद से 10 वर्षों में भारत के विकास प्रक्षेप पथ की जांच करने का काम सौंपा गया, तो अवधारणाओं और शब्दों की एक गड़गड़ाहट चेतना में उभर आई,

जैसे कि रेट्रो पंक, नीचे की सीढ़ी से ऊपर, देश को चांदी की घंटियों और कॉकल शेल्स से सजाया गया या सीधे तौर पर भ्रमित किया गया। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक सम्मेलन में अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन की जोरदार प्रशंसा के नजरिए से देखने पर कोई भ्रम नहीं है, जब उन्होंने माना कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला दशक उल्लेखनीय उपलब्धियोंष और भौतिक रूप से लाभान्वित में से एक रहा है। इतने सारे भारतीय रहते हैं. प्रधानमंत्री की नजर से देखा जाए तो संदेह और भी कम है। भारत अब अत्यधिक लोकप्रिय श्री मोदी द्वारा दी गई गारंटी से घिरा हुआ है कि वह देश को विक्सित युग में ले जाएंगे। विकास की गारंटी के बीच एक सूक्ष्म अंतर है, जो एक सतत प्रक्रिया के रूप में विकास है, और विकसित, जिसका अर्थ है उन्नत और विकसित, दूसरे शब्दों में भारत का अपने पूर्वनिर्धारित गंतव्य पर आगमन का क्षण, अर्थात, अर्थव्यवस्थाओं की विश्व रैंकिंग में तीसरा स्थान . जिस दर से भारत भर में रोजमर्रा की बातचीत में गारंटी का उपयोग किया जा रहा है, यह शब्द अगले 12 महीनों में वर्ड ऑफ द ईयर की सामान्य सूची में दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द बन सकता है। यदि ऐसा हुआ, तो यह भारतीय जनसंख्या के विशाल आकार का परिणाम होगा, जो अब अनुमानित है, सटीक नहीं, 1.44 बिलियन। (कोई नहीं जानता कि देश में कितने भारतीय हैं क्योंकि आखिरी बार जनगणना 13 साल पहले 2011 में हुई थी जब जनगणना हुई थी।) दूसरे शब्दों में, आकार मायने रखता है। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था का आकार उसकी जनसंख्या के आकार पर निर्भर करता है जितने अधिक लोग, उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था। एक अर्थव्यवस्था के रूप में पांच ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ना या विश्व रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त करना आसानी से प्राप्त होने वाला लक्ष्य है। वास्तव में, यह एक कम लटकने वाला फल है। तो, अपने करिश्माई नेता के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीसरी बार जीत की हैट्रिक बनाने के बाद विकसित भारत में पहुंचने की क्या गारंटी है? 2023 के मध्य में, विभिन्न भारत पर नजर रखने वालों के आकलन ने निष्कर्ष निकाला कि कुल 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में से कुछ नौ राज्य विकास के ष्उच्च मध्यम आय वाले देशष स्तर तक पहुंच जाएंगे। देश का दो–तिहाई हिस्सा 2030 में निम्न और मध्यम–आय स्तर के बीच झूल रहा होगा। एक–तिहाई भारतीय प्रति वर्ष 3 लाख रुपये से कम कमा रहे होंगे, जबकि दो–तिहाई लोग सालाना प्रति व्यक्ति लगभग 1.60 लाख रुपये कमा रहे होंगे। . सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2030 तक जो राज्य बेहतर स्थिति में होंगे, वे हैं तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अन्य अनुमानों में गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा शामिल हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 2028 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की श्री मोदी की गारंटी के समर्थन के बावजूद उत्तर प्रदेश और बिहार, जो अब एक बार फिर डबल–इंजन सरकार द्वारा शासित है, उनमें से एक बना रहेगा। सबसे गरीब. प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1.60 लाख रुपये से 3 लाख रुपये से कम की दूरी तय करने के लिए, यह स्पष्ट है कि मोदी सरकार के पास आय बढ़ाने और अपने अभियान के वादे को पूरा करने के लिए योजनाओं का एक बड़ा फोल्डर है, जो इस गारंटी के साथ समर्थित है कि भारत इस लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। थोड़े ही समय में विकास की अवस्था। तो, इन योजनाओं में क्या है? सभी उत्पाद या सेवा गारंटियों की तरह, श्री मोदी की गारंटियां छोटे अक्षरों में आती हैं जिन्हें बड़ी मेहनत से पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि खामियां कहां हैं। गरीबी मिटाने के वादे हैं. अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार तक पहुँचने के लिए तैयार करने के बारे में कोई वादा नहीं किया गया है। बेरोजगारी चरम पर है और लाखों शिक्षितों की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने की बेताबी को देखा जा सकता है, ऐसे में विकास की गारंटी बेरोजगारी के साथ आती है। तो फिर 800 मिलियन लोग, जो अब प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संकट निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, को मुफ्त खाद्यान्न वितरण के बिना नंगे जीवन की गारंटी कैसे दी जाएगी? ऐसा होने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को न केवल बढ़ना होगा बल्कि अभूतपूर्व दर से बढ़ते रहना होगा। उस वृद्धि को समान रूप से वितरित करना होगा।

भारतीय नौसेना के कमांड, नियंत्रण के पुनर्गठन का समय

ललित

भारत यूरोप और लेवांत के भूमि युद्धों में नौसैनिक बलों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान दे रहा है? या चीनी नौसैनिक आक्रामकता में अभूतपूर्व वृद्धि, जो दक्षिण एशिया के समुद्र तट के आसपास के समुद्र में लगातार किसी को भी शिकार बना रही है? क्या भारत भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उसके आसपास तथा नई दिल्ली के 4,104 समुद्री मील समुद्र तट से सटे द्वीपों पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और नौसेना के शत्रुतापूर्ण कृत्यों की आंच महसूस नहीं कर रहा है? यह भारत की स्थापना के लिए आपातकाल जैसी स्थिति को पहचानने का समय है जिसके लिए अपने क्षेत्र में नौसेना बलों की कमान, नियंत्रण और आगे की तैनाती के पुनर्गठन की आवश्यकता है। भारत जैसी कोई अन्य गैर–पश्चिमी नौसेना नहीं है जिसे शांतिपूर्वक तैनात किया जा सके या कम से कम 20 हिंद महासागर तटीय राज्यों की मदद करने के लिए योग्य हो, जिस तरह से भारत के नाविक बाब अल मंडेब, अरब सागर और लाल सागर के पानी में काम कर रहे हैं। मध्य पूर्व में, जबकि भारत के यहूदी राज्य के साथ अच्छे संबंध हैं और अपने अधिकांश पड़ोसियों के साथ–साथ खाड़ी अमीरात के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिनमें से सभी में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, लाल सागर में हौथी विद्रोहियों का अनियमित व्यवहार और हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकवादी समूह अप्रत्याशितता कारक लाते हैं, भले ही उनके पास भारत या इसकी पेशेवर नौसेना के साथ कोई गंभीर समस्या न हो। सबसे बड़ा अज्ञात कारक जो यूरोप और एशिया के बीच समुद्री मार्गों को प्रभावित कर सकता है, वह पीएलए नौसेना की गतिविधियां हैं – क्या इसे दक्षिण चीन सागर के आसपास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक अपने दबंग आचरण का विस्तार करना चाहिए! भारत के लिए भू–राजनीतिक परिदृश्य वास्तव में अधिक जटिल होता जा रहा है, पारंपरिक भूमि और क्षेत्रीय मुद्दे दूरगामी परिणामों के साथ पानी पर फैल रहे हैं। नवीनतम गंभीर उकसावे मालदीव के अस्थिर, अनियमित और गुमराह प्रतिष्ठान से उत्पन्न हुए हैं। अपने सामरिक महत्व को प्रदर्शित करने और समुद्र में ष्जीवन से भी बड़ीष भूमिका निभाने की उत्सुकता में, इसने अनजाने में मधुमक्खी के छत्ते को हिला दिया है। चीन को स्पष्ट रूप से भारत के ईईजेड के अंदर एक इच्छुक और लचीला लिलिपुट मिल गया है। भारतीय नौसेना को अब इन जलक्षेत्रों में और अधिक मुखर होना होगा, क्योंकि वह किसी बाहरी शक्ति के इशारे पर इस तरह के हथियार उठाने की इजाजत नहीं दे सकती। भारतीय नौसेना की कमान और नियंत्रण के पुनर्गठन और इसके बेड़े की तैनाती को संशोधित करने की आवश्यकता अत्यंत जरूरी हो गई है। नौसेना की तीन क्षेत्रीय कमान हैं, विशाखापत्तनम (पूर्व), मुंबई (पश्चिम) और कोच्चि (दक्षिण)। हालाँकि, प्रभावी रूप से, केवल पूर्व और पश्चिम ही परिचालन कमान हैं, जबकि दक्षिण प्रशिक्षण का प्रभारी

है। इस लेखक का मानना है कि नौसेना को अपने सभी अड्डों को उन्नत करके अपने विस्तार और मजबूती के लिए तैयार रहना चाहिए। बता दें कि कोच्चि प्रशिक्षण, जहाज निर्माण और रखरखाव कमान है। विजाग और मुंबई के अलावा, लैकाडिव और मिनिकॉय को लंबी दूरी और आक्रामक जहाजों, पनडुब्बियों और एयर विंग के साथ नई दक्षिण –पश्चिम नौसेना कमान बनाया जा सकता है। अंडमान ट्राई–सर्विसेज कमांड को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर कमांड बनाने के लिए इसका और विस्तार किया जाना चाहिए।

सीएए नियमों के बाद बदल रहे टकराव के स्वरूप

आसिफ

धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण अब नियम है क्योंकि कानून बदल गया है. नागरिकता चुनिंदा देशों के चुनिंदा श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जब तक कि 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम और अब अधिसूचित नियमों के तहत आवेदक मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से अलग करने वाली रेखा वहां बहुसंख्यक समुदाय के रूप में उनकी स्थिति है। हिंदू, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध, वहां अल्पसंख्यक के रूप में, सीएए और सीएआर के अंतर्गत आते हैं। स्पष्ट कथन स्वयं को यह बताने जैसा है कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव अब कोषेर है, हालांकि संविधान स्पष्ट रूप से इस तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15 में यह स्पष्ट था कि राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा। जिस क्षण सीएए के नियम लागू हुए, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत धर्मनिरपेक्ष से किसी और चीज की ओर स्थानांतरित हो रहा है, जो समय के साथ हिंदू राष्ट्र जैसा दिखने लगेगा, जिसकी कर्नाटक भाजपा के एक प्रमुख नेता अनंत कुमार हेगड़े बहुत प्रबल इच्छा रखते हैं। भारत की पहचान में धर्मनिरपेक्ष से किसी और चीज की ओर विवर्तनिक बदलाव 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उपयुक्त है। नरेंद्र मोदी सरकार अपनी 2019 की गारंटी को पूरा कर रही है कि नए नागरिकता नियम उन इलाकों को लक्षित करते हुए लागू किए जाएंगे जहां बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेश से आए थे, खासकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पूर्वोत्तर में अन्य जगहों पर। अधिसूचना इस बात की पुष्टि थी कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने वादे पूरे करती है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और मल्लिकार्जुन खड़गे और छोटे और क्षेत्रीय दलों की ओर से आई प्रतिक्रियाओं से ध्रुवीकरण स्पष्ट है। इंडिया गुट नागरिकता कानून में बदलाव के खिलाफ है, जबकि बीजेपी इसकी सफलता पर खुशी मना रही है। परिवर्तन का असर अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल और असम की राजनीतिक गतिशीलता पर अधिक पड़ेगा। जबकि पश्चिम बंगाल में इसे लागू करना सीधा है, असम में इसने बंगाली भाषियों की उपस्थिति के प्रति हिंसक रूप से शत्रुतापूर्ण जातीय समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, चाहे वे हिंदू हों या मुस्लिम। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भले ही विरोध को गुमराह बताने की कोशिश करते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि बंगाली भाषियों को नागरिकता देने का भाजपा का कदम ध्रुवीकरण कारक है, न कि आवेदकों की धार्मिक पहचान। पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ने भले ही बदलाव को ष्लॉलीपॉपष कहकर खारिज कर दिया हो, लेकिन वह इस संभावना के प्रति सतर्क थीं कि 10 मार्च को ऐसा कुछ होगा, जब उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक मेगा रैली को संबोधित किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि पश्चिम बंगाल में किसी भी हिरासत केंद्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर गणना प्रक्रिया के कार्यान्वयन को रोकने की कसम खाई। सुश्री बनर्जी का तर्क है कि सीएए अनावश्यक है। बांग्लादेश से आए अनुसूचित जाति मतुआ समुदाय के हिंदुओं के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड हैं, वे सरकार और रक्षा सेवाओं में काम करते हैं, और विधायक, सांसद और पंचायत और नगर निकाय के सदस्यों के रूप में चुने गए हैं। उनका दावा है कि भाजपा ने मतुआ समुदाय के भोले–भाले लोगों को यह कहानी निगलने के लिए उकसाया है कि सीएए जीवन रक्षक है। 2015 तक बांग्लादेश से सीमा पार करके आए हिंदुओं की स्थिति को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव वफादारी वोट बनाने को लेकर है. बीजेपी भी इन वोटरों को चाहती है और टीएमसी भी. मूल बात यह है कि मतुआ एक समरूप वोट बैंक नहीं हैं। इस प्रकार, भाजपा और टीएमसी दोनों को उन्हें लुभाना होगा। लॉलीपॉप आते रहना है. इसलिए ष्गारंटीष नई मुद्रा है जिसमें राजनीतिक नेता मतदाताओं के सामने अपनी विश्वसनीयता की पुष्टि करते हैं, जो स्पष्ट रूप से एक या दूसरे पक्ष के साथ खुले तौर पर पक्ष लेने से खुद को होने वाले फायदे की गणना करते हैं। ममता बनर्जी ने ब्रिगेड रैली में अपने गारंटी कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें पश्चिम बंगाल में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं होने की नकारात्मक गारंटी भी शामिल है। यानी उत्तर से दक्षिण बंगाल तक फैले लगभग 16–17 संसदीय क्षेत्रों में, समर्थन हासिल करने के लिए ममता बनर्जी की जोरदार प्रतिबद्धता है। 2024 में, मुट्ठी भर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतुआ वोट जितना महत्वपूर्ण है, मुस्लिम वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मटुआ और मुस्लिम मतदाताओं पर अपना रुख घोषित करने के लिए ममता बनर्जी पर दबाव डालकर, भाजपा को स्पष्ट रूप से हिंदू मतदाताओं से नकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद है, जिन्होंने यह लालच निगल लिया है कि बहुसंख्यक समुदाय के रूप में उनकी स्थिति टीएमसी की तुष्टिकरण की राजनीति और उससे पहले के कारण खतरे में है। वामपंथी दल और कांग्रेस. दो सप्ताह में, पश्चिम बंगाल ने चार बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की है क्योंकि वह भाजपा के लिए 370 सीटों और सहयोगियों के साथ 543 ई में से कुल 400 सीटों के अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। लोकसभा में निर्वाचित सीटें. यह अलग बात है कि भाजपा ने इसी अवधि में पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 40 सीटें जीतने की अपनी उम्मीदों को घटाकर 25 सीटें कर दिया है। लक्ष्य के रूप में निर्धारित सीटों की संख्या की परवाह किए बिना प्रतिस्पर्धा और टकराव कम भयंकर नहीं है। मतदाताओं को हाथ में मौजूद पक्षी यानी ममता बनर्जी की गारंटी और झाड़ी में रहने वाले पक्षी यानी मोदी सरकार की गारंटी के बीच विकल्प दिया जा रहा है। ऐसी सरकार और प्रशासन के बीच एक विकल्प की पेशकश करना जो पहुंच योग्य हो।

गर्ल आइकान प्रोग्राम में 52 किशोरियों को स्मार्टफोन वितरण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। मिलान फाउंडेशन एवं सरजू प्रसाद शैक्षिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा गर्ल आइकन प्रोग्राम बीआरपी इंटर कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य डॉक्टर सुबाष चंद्र सिंह कार्यक्रम अधिकारी को लेकर 52 किशोरियों को गर्ल आइकन कार्यक्रम से जोड़ा गया है ये किशोरिया अपने हम उम्र पियर समूह द्वारा समुदाय में लड़कियों की शिक्षा हेतु जागरूक करेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संजय उपाध्याय पूर्वअध्यक्ष चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने कहा कि गर्ल आईकॉन प्रोग्राम किशोरियों को ट्रेनिंग मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य डिजिटल साक्षरता और करियर काउंसलिंग के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। नेहा श्रीवास्तव उजमा और मुन्नी बेगम ने बताया कि संस्था वंचित समुदाय की किशोरियों को सूशिक्षित सुयोग्य और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है मिलान द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय कार्यक्रम गर्ल आइकन कार्यक्रम है। परिणीता व सुपूर्णा ने बताया कि किशोरियों के शिक्षा हेतु गर्लआईकान प्रोग्राम के तहत 52 किशोरी को स्मार्टफोन बैग और टीशर्ट वितरित किया गया है।कार्यक्रम का सफल संचालन सुरभि श्रीवास्तव और अनुभव ने किया। कार्यक्रम में बालिकाओं के अभिभावक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नेहा श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों का पुष्प गुछ देकर स्वागत किया । उक्त अवसर पर ऋषि श्रीवास्तव मुन्ना मौर्य विनय यादव विवेक सुरभि उजमा सुपर्णा रंजना अनुभव परिणीता शामिल रही।संजय उपाध्याय ने सभी अतिथियों काआभार व्यक्त किया।

नेहा श्रीवास्तव एवं सुरभि श्रीवास्तव द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि डॉ सुबाष चंद्र सिंह ने कहा कि किशोरी सशक्तीकरण के तहत उनके लीडरशिप एवं कैपेसिटी बिल्डिंग शिक्षा की क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा और नई दिशा व नई रोशनी प्रदान करेगा। जौनपुर जनपद की किशोरियों के लिए यह एक बड़ा अवसर है । रंजना शुक्ला एवं सुरभि श्रीवास्तव ने बताया कि किशोरी सशक्तीकरण लीडरशिप

खेल मंत्री ने स्टेडियम में विभिन्न खेल परियोजनाओं का किया शिलान्यास

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर । खेल के क्षेत्र में चहुंमुखी विकास के लिए राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण, उ0प्र0 द्वारा जनपद के खेल अवस्थापनाओं के विकास के लिए 2886.97 लाख की परियोजनाओं की सौगात प्रदान किया जिसका 15 मार्च 2024 को शिलापट्ट का अनावरण किया गया।

शिलापट्ट अनावरण कार्यक्रम में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ''खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत'' रू0 995.5 लाख की लागत से स्वीकृत बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल जिसमें 40 20 मी0 का एक 13 08 मी0 का एक 22 13.5 मी0 का एक इस प्रकार कुल 03 बहुउद्देशीय हाल रहेंगे, जो लिफ्ट से सुविधायुक्त होगा। राज्य योजनान्तर्गत जनपद के धावकों के लिए 865.92 लाख की लागत से स्वीकृत कृत्रिम सतह के धावनपथ के शिलापट्ट का भी अनावरण किया गया। धावन पथ में 400 मी0 के 8 लेन की सुविधा के साथ स्टीपल चेज हेतु वाटर जम्प एवं विभिन्न प्रक्षेप स्पर्धाओं के लिए केज भी सम्मिलित है। इन परियोजनाओं के साथ ही राज्य योजनान्तर्गत जनपद के पहले आधुनिक तरणताल का भी शिलापट्ट का अनावरण किया गया जिसकी लागत रू0 487.46 लाख है। तरणताल में दो तरणताल निर्मित किये जायेंगे जिसमें नौसिखिया एवं तैराक के सिखने की सुविधा एक साथ रहेगी। तरणताल में दर्शक दीर्घा, चेंज रूप एवं आपदा प्रबन्धन कक्ष का भी निर्माण किया जायेगा।

इस अवसर पर खेल मंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही जनपद में अत्याधुनिक जिम की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी जिससे खिलाड़ियों के मांसपेशियों में चोट आदि से निवृत्ति मिलेगी। उक्त जानकारी क्रीडा अधिकारी डा0 अतुल सिन्हा ने दी है।

पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत शुक्रवार देर रात चेकिंग के दौरान शाहगंज,सरपतहाँ व खुटहन थाने की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा शातिर चोरध्नकबजन अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से एक बाइक तमंचा कारतूस बरामद हुआ है।बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में थानाध्यक्ष शाहगंज बाल बाल बचे।पुलिस पकड़े गए बदमाश के अन्य फरार साथियों की तलाश में जुटी है।

घटना के मामले में शनिवार को जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकार शाहगंज अजीत सिंह चौहान ने बताया कि शुक्रवार की रात थानाध्यक्ष शाहगंज तारकेश्वर राय व त्रिवेणी सिंह थानाध्यक्ष सरपतहाँ पुलिस बल के साथ अभियान चलाते हुए संयुक्त टीम बनाकर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान सुल्तानपुर मार्ग से आती हुई एक बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल दिखाई दी।जिसे पुलिस बल ने रोकने का इशारा किया। पुलिस चौकिंग देख बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा खुटहन रोड पर मोटर साइकिल मोड कर भागने लगें,जिसकी सूचना वायरलेस द्वारा कंट्रोल रूम को दी गयी ,सूचना पर थानाध्यक्ष खुटहन अरविंद कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ सामने से आकर भागते हुये बदमाशों का घेराव किया, तो बदमाश अपने को

घिरता देखकर पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें थानाध्यक्ष शाहगंज तारकेश्वर राय बाल बाल बचे।पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गयी, जिससे बदमाश घायल होकर गिर पड़ा तथा अन्य बदमाश अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार जिला अस्पताल भेजे दिया गया है।पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम रविन्द्र वर्मा पुत्र सभापति वर्मा निवासी मकदूमपुर थाना खुटहन जनपद–जौनपुर बताया पकड़े गए बदमाश के अन्य फरार साथियों की तलाश में पुलिस जुट गई है।पकड़े गए बदमाश रविन्द्र वर्मा का लंबा आपराधिक इतिहास है उसके ऊपर बिभिन जनपदों में चार दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है।

अवध कॉलेजिएट की मोहान रोड एवं पारा शाखा का वार्षिक उत्सव मनाया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। अवध कॉलेजिएट की मोहान रोड शाखा एवं पारा शाखा का वार्षिक उत्सव मोहान शाखा के प्रेक्षागृह में धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना से हुआ। प्रबंधन सर्वजीत सिंह ने निदेशिका जतिंद ंवालिया ,व प्रधानाचार्य अमृता धनाईं व शिक्षकों के साथ सरस्वती वंदना करते हुए माल्यार्पण किया। तत्पश्चात बच्चों ने अवध एंथम का गायन किया ।

प्रबंधक सर्वजीत सिंह ने अपने अभीभाषण मे कहा कि अभिभावक अपने बच्चो को विद्यालय मे प्रवेश कराकर सारी चिताओं से अपने आप को मुक्त समझता है जबकि मैं समझता हूं कि विद्यालय के साथ–साथ बच्चे की सर्वांगीण विकास में माता–पिता का भी पूर्ण सहयोग होता है। इसी क्रम मे उन्होंने कहा कि रामगढ़ शाखा की जाह्नवी पटेल ने यूपीएससी की आई एस एस परीक्षा मे आल इंडिया लेवल पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। दरोगा खेडा शाखा की रुचि सिंह ने यूपीएससी की पीसीएस परीक्षा पास कर डिप्टी जेलर के पद पर सुशोभित हुई इसके अतिरिक्त दो भूतपूर्व छात्रों ने आकाश दीक्षित एवं अतुल गिरी ने जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर सुशोभित होकर विद्यालय का नाम रोशन किया।

प्रबंधक सर्वजीत सिंह निदेशिका जतिंद ंवालिया ने गत वर्ष के मेधावी छात्राओं को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जिसमें विद्यालय के 9 टॉपर्स को मोबाइल फोन एवं 96: से अधिक लाने वाले 10 को 5100 /– की नगद धनराशि एवं 92: से अधिक लाने वालों 28 बच्चो को साइकिले एवं 88: से अधिक लाने वाले 38 को सट्रॉली बैग देकर सम्मानित किया । कक्षा मे प्रथम, द्वितीय, व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चो को नगद पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम का प्रसंग विषय ''पंखों से परे'' बियोंड विंग्स पर आधारित था। विद्यालय निदेशिका जतिंद ंवालिया एवं संयुक्त निदेशिका ब्रह्मजोत कौर ने मेधावी छात्राओं की माताओ का सम्मान उन्हें मदर क्वींन की उपाधि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में कई रंगारंग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम् गायन से किया गया।

नि:शुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'शाहजहांपुर' शनिवार को ददरौल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सपा से संभावित प्रत्याशी ठाकुर लखन प्रताप सिंह के सौजन्य से ग्राम पंचायत भरगवां, ग्राम पंचायत इटौरा व साहबगंज में एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें काफी संख्या में मरीजों के नेत्रों का परीक्षण किया गया और देखभाल के सुझाव दिए गये। शिविर में मौजूद संबंधित डॉक्टर ने बताया कि अधिकांश लोगों की आँखों में एलर्जी व धूल मिट्टी से संक्रमण पाया गया। मौसम में बदलाव की बजह से भी आँखों में खुजली तथा लालिमा जैसी सीजनल एलर्जी भी पाई गई। उन्होंने बताया कि नेत्र हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है इसलिए हमें इनकी देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। समय समय पर अपनी आंखों की जांच करवानी चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक ठाकुर लखन प्रताप सिंह ने बताया कि जनहित में इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी ओर से लगातार चलाये जा रहे हैं। जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। और उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य है। इस अवसर पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण, दवाएं एवं चश्मे वितरित किये गये।

बस्तर - द नक्सल स्टोरी

नक्सलवाद के कड़वे सत्य को उजागर करती फिल्म – मृत्युंजय दीक्षित

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना)

"द केरल स्टोरी" फेम सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल शाह प्रोडक्शन की फिल्म" बस्तरः द नक्सल स्टोरी", बस्तर में नक्सली हिंसा तथा वहां के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित और प्रमुख रूप से एक "मां" की शक्ति को समर्पित शानदार फिल्म है। फिल्म के आरम्भ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र का एक परिवार राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत होकर 15 अगस्त के दिन एक विद्यालय में तिरंगा फहराता है और "जन गण मन" का गायन करता है किंतु खूंखार नक्सलियों को इसका पता चल जाता है और नक्सली उस परिवार को अपनी अदालत में उठा लाते हैं जहाँ तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति के शरीर के 32 टुकड़े कर दिये जाते हैं । मारे गए व्यक्ति की पत्नी कहती है," मैं रत्ना कश्यप, मेरे पति मिलन कश्यप को नक्सलियों ने मार दिया ,पूरे गांव के सामने 32 टुकड़े कर दिये और उसके खून से अपने शहीद स्तंभ को मेरे हाथों से रंगवाया। क्या गलती थी उसकी, बस यही कि उसने 15 अगस्त को अपने गांव के स्कूल में भारत का झंडा लहराया। बस्तर में भारत का झंडा लहराना एक जुर्म है जिसकी सजा दर्दनाक मौत है।" मेरे बेटे को भी उठाकर ले गये उसे भी नक्सली बनाएंगे। हर परिवार से एक बच्चा उनको देना पड़ता है नहीं देते तो पूरे परिवार को मार देते हैं।अरे हम बस्तर की मांएं करें तो करें क्या , मैं मेरे पति का बदला और अपने बेटे को वापस लाने के लिए जिंदा हूं। "मैने हथियार उठा लिए हैं बस्तर से इन नक्सलियों को समाप्त करके रहूंगी।" यही फिल्म की पार्श्वभूमि है ।

आगे बढ़ते हुए फिल्म बताती है कि किस प्रकार नक्सली देश को कम से कम 30 टुकड़ों में बांटने का खतरनाक षड़यंत्र रचते रहते हैं, भारत के मजबूत लोकतंत्र को कमजोर दिखाने के लिए वामपंथी तत्व किस प्रकार अपना नैरेटिव चलाते हैं और इस भारत विरोधी अभियान के लिए विदेशी फंडिंग आती है । इनकी घुसपैठ देश के सामाजिक व राजनैतिक ताने –बाने को प्रभावित करने वाली सभी संस्थाओं यथा विश्वविद्यालयों ,न्यायपालिका व मीडिया जगत में है। निहित स्वार्थों की पूर्ति करने व छत्तीसगढ़ की अकूत सम्पदा पर कब्जा करने के लिए कुछ लोग नक्सली हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे और बस्तर के गांवों में विकास नहीं हो पा रहा था। सरकारी पक्ष के वकीलों के पास तमाम सबूत होने के बाद भी कोर्ट वामपंथ के वकील के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है और सरकारों की विकृत राजनीति व मनोदशा के कारण नक्सलवाद की हिंसा से प्रभावित पीड़ितों पर हुए भीषणतम अत्याचारों की घटनाओं की जांच के बजाए कोर्ट आईपीएस अधिकारी नीरजा माधवन (अदा शर्मा)के खिलाफ ही न्यायिक जांच आयोग गठित कर दिया जाता है।

लगभग 124 मिनट लंबी फिल्म में नाक्साली हिंसा के दिल दहलाने वाले क्रूर दृश्य हैं जिसके कारण फिल्म को "ए" सार्टिफिकेट दिया गया है। फिल्म की नायिका अदा शर्मा ने आईपीएस अधिकारी नीरजा माधवन के रूप में अत्यंत सशक्त अभिनय किया है जो भारत को हर प्रकार के नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए दृढ़संकल्पित हैं। फिल्म "बस्तर" में की महिला सिर्फ एक "मां" या फिर पत्नी नहीं है वह एक ऐसी योद्धा है जिसके युद्ध का तात्पर्य है अमानवीय क्रूरता का सामना करना।

फिल्म का प्रत्येक दृष्य व कहानी वास्तविक घटनाओं तथा तथ्यों से प्रेरित है। फिल्म मानवता को झकझोरने, आम जनमानस को नक्सलवाद के खिलाफ खड़ा करने तथा राष्ट्र के समक्ष वामपंथ की विकृत विचाराधारा का खुलासा करने में समर्थ है।

बस्तर में नक्सली हिंसा की सबसे अधिक शिकार महिलाएं हुयी हैं। नक्सली आतंक स्त्रियों के लिए आईएसआईएस और बोको हरम जितने ही खतरनाक हैं । फिल्म में बस्तर में सीआरपीएफ के 76 जवानों की निर्मम हत्या की घटना और उसके पश्चात जेएनयू जैसे विश्व विद्यालयों में माने गए जश्न को भी शामिल किया गया है।

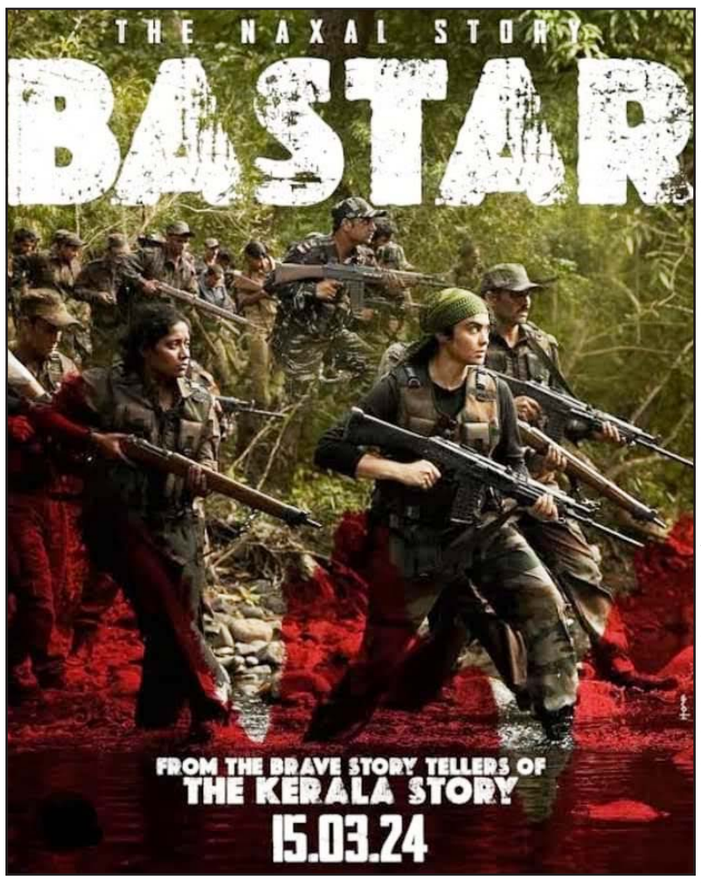

नक्सलियों के आतंक के खात्मे लिए आईपीएस नीरजा माधवन (अदा शर्मा) पूरी ताकत से लड़ रही है । फिल्म के अंत में नीरजा माधवन के संवाद बहुत ही सशक्त और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हैं। फिल्म के सभी किरदारों ने सशक्त अभिनय किया है, फिल्म की गति इसे कभी उबाऊ नहीं होने देती । नायिका अदा शर्मा के अतिरिक्त वामपंथी वकीलों की भूमिका में राम्या सेन ,अंगसा बिश्वास और रत्ना की भूमिका में इंदिरा तिवारी छाप छोड़ती हैं । फिल्म का गीत वंद वीरम दिल को छू रहा है ।

निर्देशक सुदीप्तो सेन का कहना है कि यह फिल्म दस वर्षे के गहन शोध का परिणाम है। सुदीप्तो ने माओवादी संघर्ष को काफी नजदीक से देखा है। उनका कहना हे कि माओवादी संघर्ष 1957 से प्रारम्भ हुआ और अब तक अकेले बस्तर जिले में ही 17 हजार पुलिस जवान हीशद हो चुके हैं। यह फिल्म वामपंथ की उग्र विचारधारा की असलियत जनमानस के सामने खोल रही है जिसके कारण वामपंथी विचारधारा वाले लोग निर्माता निर्देशक की आलोचना कर रहे हैं ।

देश की एक बड़ी समस्या नक्सलवाद को समझने के लिए ये फिल्म प्रत्येक भारतीय को देखनी चाहिए।

वामपंथी स्वाभाविक रूप से इसका विरोध करेंगे और अपने नेटवर्क के माध्यम से इसकी नकारात्मक समीक्षा कराएँगे, किन्तु अब दर्शक भी जाग चुका है और ऐसी समीक्षाओं में नहीं फंसता दृ द कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी, आर्टिकल 370 की बम्पर सफलता इसका प्रमाण है।

लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिलाधिकारी ने एफएसटी व एसएसटी टीमों व अधिकारियों से किया संवाद

हरदोई(अम्बरीष कुमार सक्सेना) लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही आज रसखान प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने एफएसटी व एसएसटी टीमों से संवाद किया। जिलाधिकारी ने कहा कि टीमों के सम्बंधित अधिकारी एक दूसरे से भली भांति परिचित हो लें। आचार संहिता लागू होते ही एफएसटी टीमे सक्रिय हो जाएं। दायित्वों के निर्वहन में कोई लापरवाही क्षम्य नही होगी। एसएसटी टीमे अपनी पाली में समय पर ड्यूटी पर पहुंचें। व्हाट्सऐप ग्रुप पर लगातार सक्रिय रहें। निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारियों के मोबाईल नंबर अपने पास रखें। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। दायित्वों के निर्वहन में पूरी सतर्कता रखी जाये।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी चुनाव के अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करें। सेक्टर मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करें कि बीएलओ ने 12डी फॉर्म वितरित कर दिया है। चुनाव दिवस की प्रक्रिया की चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि मॉक पोल तक केवल वही मशीन बदली जाएगी जो खघ्राब होगी। वास्तविक मतदान के दौरान यदि बीयू या सीयू खघ्राब है तो पूरा सेट बदला जायेगा। यदि वीवीपैट खघ्राब है तो केवल वीवीपैट बदला जायेगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान टीमों के साथ निरंतर संपर्क में रहें। चुनाव के दौरान प्रत्येक 2 घंटे में एमपीएस ऐप पर सूचनाएं भरी जानी हैं। मतदान प्रारम्भ होने की सूचना इसी ऐप के माध्यम से दी जानी है। आदर्श आचार संहिता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आचार संहिता के दौरान कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम बिना अनुमति के नही होगा। प्रचार के

दौरान किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसके मकान या भूमि पर कोई झंडा, बैनर या पोस्टर नही लगाया जायेगा। धारा 144 का उल्लंघन करने पर संगत धारा में मुकदमा दर्ज किया जायेगा। किसी राजनीतिक दल द्वारा अन्य दल के उम्मीदवारों का पुतला नही जलाया जायेगा। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में त्वरित कार्रवाई की जाये। मतदान के दिन बूथ के अंदर किसी अधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने बूथों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी रखें। मतदेय स्थलों में मानक के अनुरूप सुविधाओं की जाँच कर सूचना निर्धारित प्रारूप पर भरकर अगले तीन दिन में प्रेषित की जाये। मतदान पार्टियों की रवानगी स्थल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरदोई लोकसभा के लिए सीएसएन कॉलेज व मिश्रिख लोकसभा के लिए आईटीआई परिसर निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट निर्वाचन से जुड़े सम्बंधित अधिकारियों का नंबर अपने पास रखें। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी अधिकारी अवकाश पर नही जायेगा। पुलिस अधीक्षक केशव चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि सेक्टर पुलिस अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट का सहयोग करें। दोनों अधिकारी एक साथ भ्रमण करें। दोनों अधिकारी ईवीएम जमा होने तक साथ अवश्य रहें। सुरक्षा में कोई चूक क्षम्य नही होगी। पुलिस अधीक्षक केशव चन्द्र गोस्वामी ने कहा कि एफएसटी टीमों में लगे पुलिस अधिकारी रिलीवर के आने पर ही अपना कार्यस्थल छोड़ें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक केशव चन्द्र गोस्वामी, मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, वरिष्ठ कोषाधिकारी अनुराग द्विवेदी आदि उपस्थित रहे।

लखनऊ विश्वविद्यालय के 12 छात्रों का बेवन साल्यूशन एवं एचसीएल कंपनी मे हुआ प्लेसमेंट

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के 12 छात्र–छात्राओं को बेवन सॉल्यूशन एवं एचसीएल कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ।

चयनित छात्रों को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार राय

और संकाय के डीन प्रो. ए. के. सिंह ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। प्लेसमेंट इंचार्ज डॉ. हिमांशु पाण्डेय ने बताया कि बेवन सॉल्यूशन कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में एमबीए की 2 छात्राओं (रितिका सिंघल, अंकिता मजूमदर) और बीटेक की 1 छात्रा (अपर्णा) का चयन 3.0 लाख प्रतिवर्ष के पैकेज पर टैलेंट स्काउट (यूएस स्टॉफिंग एंड रिक्रूटमेंट) पद पर हुआ साथ ही एचसीएल टेक कंपनी में बीकॉम की 3 छात्राओं (रिया जयवाल, अनुराधा शुक्ला, खुशी शर्मा), बीसीए के 2 छात्रों (क्षितिज रस्तोगी, रिफात हुसैन), बीए के 2 छात्रों (आर्यन अवस्थी, काजल मिश्रा), बीएससी के 1 छात्र (प्रखर सिंह यादव) और बीवीए के 1 छात्र (जीशान रेहमान) का चयन 2.40 लाख प्रतिवर्ष के पैकेज पर टेक्निकल सपोर्ट एनालिस्ट पद पर हुआ।

सहकारिता राज्यमंत्री ने सहकारिता भवन पीसीयू सभागार में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के विभिन्न अंचलों में निर्मित होने वाले गोदामों का किया वर्चुअल शिलान्यास

–उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 एवं यूपीसीएलडीएफ द्वारा निर्मित होने वाले 100 मै0 टन क्षमता के 43 गोदाम, 250 मै0 टन क्षमता के 11 गोदाम एवं 1000 मै0 टन क्षमता के 09 गोदाम का वर्चुअल शिलान्यास किया।

–गोदामों के निर्माण होने से भण्डारण क्षमता में वृद्धि होगी।

–गोदामों का उपयोग साधन सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की उपज फसल एवं उर्वरकों का भण्डारण किया जायेगा – जे0पी0एस0 राठौर

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे0पी0एस0 राठौर ने आज दोपहर 12 बजे सहकारिता भवन लखनऊ के पीसीयू सभागार में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार

के सौजन्य से प्रदेश के विभिन्न अंचलों में उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यूपीआरएनएसएस) एवं यूपीसीएलडीएफ द्वारा निर्मित होने वाले 100 मै0 टन क्षमता के 43 गोदाम, 250 मै0 टन क्षमता के 11 गोदाम एवं 1000 मै0 टन क्षमता के 09 गोदाम का वर्चुअल शिलान्यास किया। इसके अतिरिक्त जिला सहकारी बैंक लि0 शाहजहांपुर शाखा सिधौली का वर्चुअल लोकार्पण भी किया।

इसके अतिरिक्त सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे0पी0एस0 राठौर ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉपरेटिव एण्ड कॉर्पोरेट मैनेजमेन्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (आई0सी0सी0एम0आर0टी0) रिंग रोड, इंदिरानगर, लखनऊ के प्रांगण में कृषि विज्ञान अन्वेषण केन्द्र का भी शिलान्यास किया।

उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक ए0के0 सिंह ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में प्राप्त 100 मै0 टन के 103 गोदामों के सापेक्ष प्रथम चरण में 43 गोदामों का वर्चुअल शिलान्यास मा0 मंत्री जी द्वारा किया गया, शेष गोदामों का शिलान्यास द्वितीय चरण में किया जायेगा। सरकार की मंशा के अनुरूप निर्माण कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ किया जायेगा।

इस अवसर पर सहकारिता राज्यमंत्री ने कहा कि इन गोदामों के निर्माण होने से भण्डारण क्षमता में वृद्धि होगी। गोदामों का उपयोग साधन सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की उपज फसल एवं उर्वरकों का भण्डारण किया जायेगा। लंबी अवधि के भंडारण के लिए एवं उत्पादों की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए किया जायेगा। इससे खाद्यान्न एवं उर्वरक पूर्ण सुरक्षित रहेगा। कार्यक्रम में दीपिका सिंह व शहरीन सिद्दीकी को ड्रोन एवं इलेक्ट्रानिक वाहन दिया गया। कार्यक्रम में सहकारिता के विकास की झलक पर आधारित एक फिल्म भी दिखाई गयी।

अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (ग्रा0गो0) सहकारिता श्रीकान्त गोस्वामी ने आये हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

वर्चुअल शिलान्यास के अवसर पर आयुक्त एवं निबंधक सहकारिता श्री अनिल कुमार, अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक (बैकिंग) एकता सिंह, पी0सी0एफ0 के प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार, यू0पी0 सी0एल0 डी0एफ0 के प्रबंध निदेशक राम प्रकाश, एलडीबी के प्रबंध निदेशक राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ तथा समस्त यू0पी0 आर0एन0 एस0एस0 अधिकारीध्कर्मचारी तथा इसके अतिरिक्त आईसीसीएमआरटी में आयोजित कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक श्री आलोक दीक्षित एवं अन्य अधिकारीध कर्मचारी उपस्थित रहे।

श्री जयनारायण मिश्र, महाविद्यालय, केकेसी, में संस्थापक दिवस समारोह आयोजित

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। श्री जयनारायण मिश्र, महाविद्यालय, केकेसी, में संस्थापक दिवस समारोह का आयोजन नवीन भवन स्थित उत्सव स्थल में किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, ने समारोह का शुभारंभ मॉ सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, सन 1917 में स्थापित यह संस्था वर्तमान समय में भी आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाते हुए समकक्ष महाविद्यालयों में अपना विशेष स्थान बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि 80 से 90 तक के दशक में यहां के हालात कुछ अलग थे किंतु 90 दशक से अब तक महाविद्यालय ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उन्होंने महाविद्यालय द्वारा विगत वर्षों में प्राप्त शैक्षणिक, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियो, शोध, प्रोजेक्ट्स तथा प्लेसमेंट एवं इंटर्नशिप से जुड़ी उपलब्धियां के लिए यहां के प्रबंध तंत्र एवं शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय से उनका पुराना और आत्मीय जुड़ाव है। भविष्य में महाविद्यालय के विकास एवं संचालन से जुड़े किसी भी कार्य के लिए उनका सहर्ष योगदान रहेगा। उन्होंने महाविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी अपना सहयोग देने की बात रखी। उन्होंने युवा छात्र–छात्राओं को मंच से प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जिन बच्चों को आज मेडल मिला है यह उनकी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने युवा छात्र–छात्राओं से आगे आकर राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करने का आह्वान किया।इस अवसर पर मुख्य अतिथि, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत गत वर्ष 2022–23 में उत्तीर्ण हुए छात्र–छात्राओं को अपने कर कमलो से मोबाइल देकर महाविद्यालय में वितरण कार्य का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका, ज्योति किरण एवं जर्नल, कॉमर्स टुडे, विचार, लॉ रिव्यू, साइंस रिवीलिएशन, टॉर्च बेयर्र्स का विमोचन किया। उन्होंने मेडल पाने वाले छात्र–छात्राओं को मेडल तथा सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित भी किया। उन्होंने उन छात्रों का विशेष रूप से उल्लेख किया जिन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी पदक प्राप्त हुए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, वी.एन. मिश्र ने कहा कि, उन्हें प्रसन्नता होगी यदि यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाए। उन्होंने महाविद्यालय प्राचार्य को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

महाविद्यालय मंत्री प्रबंधक, जी. सी. शुक्ला ने अतिथियों का स्वागत किया एवं मेडल पाने वाले छात्र छात्राओं को बधाइयां दी ।

महाविद्यालय प्राचार्य, प्रो विनोद चंद्रा ने इस अवसर पर महाविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सभी के समक्ष रखी। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय में मीडिया एवं फिल्म केंद्र की स्थापना आगामी सत्र में की जाएगी। साथ ही साथ गांधियन स्टडीज एवं सेंटर फॉर चाइल्ड एंड यूथ डेवलपमेंट विषयों पर भी महाविद्यालय में कोर्स आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने मेधा संवर्धन तथा दिव्यांकुर जैसी सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं को और बड़े कैनवास पर लाने की बात की। इस अवसर पर प्राचार्य ने विश्वविद्यालय एवं प्रादेशिक स्तर पर उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की चर्चा की। साथ ही साथ महाविद्यालय के प्लेसमेंट एवं ट्रेनिंग सेल द्वारा वर्ष भर में 700 से ज्यादा इंटर्नशिप तथा 300 से ज्यादा जॉब ऑफर्स की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में कई बड़े व्यावसायिक संगठनों के साथ प्लेसमेंट एवं ट्रेनिंग में एम ओ यू साइन होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी सत्र में एक इनक्यूबेशन सेंटर एवं एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रशिक्षण केंद्र, राजकीय सहयोग से स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं को रोजगार परक शिक्षा के वातावरण को परिणाम दायक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए भविष्य की योजनाओं से भी अवगत कराया।

सत्र 2022–23 के लिए,अमन स्वर्णकार को अध्यक्ष पदक एवं सुष्मिता सन्यवाल को प्राचार्य पदक से सम्मानित किया गया। कैडेट यशवेन्द्र विश्वकर्मा एवं गगनदीप कौर को बेस्ट एनसीसी कैडेट का अवार्ड मिला।

हर्षवर्धन को बेस्ट एनएसएस वालंटियर का अवार्ड मिला। हर्ष सिंह एवं ज्योति माली को बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड मिला। सौम्या शुक्ला को सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक प्रतिभा का अवार्ड मिला। समारोह में कुल 62 पदकों का वितरण किया गया।

समारोह में गत वर्ष रिटायर हुए शिक्षकों, प्रो मीता साह एवम प्रो एस एल ए खान, को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दुशाला एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

प्रो. पायल गुप्ता ने कार्यक्रम का संचालन किया। उप प्राचार्य प्रो के के शुक्ला ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष, गोपाल नारायण मिश्र,सहायक मंत्री प्रबंधक, श्रो सन्मय शुक्ला, सदस्य माधव लखवानी सहित शिक्षक, कर्मचारी गण एवं छात्र–छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

लखनऊ लोकसभा के अंतर्गत सांसद प्रतिनिधियों द्वारा कई कार्यो का शिलान्यास किया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री व सांसद लखनऊ के प्रयासों से गोमती नगर जनकल्याण महासमिति की मांग पर विवेक खंड में सामुदायिक केंद्र एवं डे केयर सेंटर सीनियर सिटीजन का शिलान्यास एमएलसी मुकेश शर्मा के द्वारा एवं विनीत खंड में ई लाइब्रेरी का शिलान्यास डॉ राघवेंद्र शुक्ल प्रतिनिधि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। श्री शुक्ला ने बताया कि लखनऊ लोकसभा के अंतर्गत आज 3 ई लाइब्रेरी ,7 सामुदायिक केंद्र,और 5 ग्रीन करीडोर का शिलान्यास आज 12रू30 बजे से पहले हो जाएगा एवम श्री शुक्ल ने बताया कि रक्षामंत्री के लखनऊ के हुए कार्य जैसे विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन ,एयरपोर्ट टर्मिनल 3 ,आउटर रिंग रोड के उद्घाटन लखनऊ लोकसभा के सभी रेलवे क्रासिंग पर आरओबी या अंडरपास का शिलान्यास और एवम भविष्य की परियोजनाएं जैसे शहीद पथ पर एलिवेटेड रोड,गोमती नगर में सबसे बड़ा ड्योग्नोटिक जैसे अन्य कार्यों के बारे में सभी को जानकारी दी और पुनः सभी से निवेदन किया है कि इस बार भारी से भारी संख्या में राजनाथ सिंह को वोट देकर विजई बनाएं उक्त कार्यक्रम में डॉ राघवेंद्र शुक्ल, अभिषेक राय मंडल अध्यक्ष,संजय राठौर पार्षद ,अरुण राय पार्षद , पंडित यज्ञदेव शर्मा,कर्नल ए एन पांडेय कार्यकारी महासचिव , पीआर पांडेय, वी के जौहरी ,संजय निगम,जीएस यादव ,दीपा टंडन मनोज कुमार मिश्रा बहन नंदिनी मिश्रा पूरी टीम के साथ,लक्ष्मी धामी,लक्ष्मी,दीपा नेगी, एके बागी, वा विनीत खंड के वरिष्ठ एवं सम्मानित जन उपस्थित रहे।

निदेशक प्रो0 सी0एम0 सिंह डा0 रा0म0लो0आ0सं0 द्वारा थैलेसीमिया डे केयर सेन्टर का भ्रमण किया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। निदेशक प्रो0 सी0एम0 सिंह डा0 रा0म0लो0आ0सं0 द्वारा दिनाक 16 मार्च 2024 को थैलेसीमिया डे केयर सेन्टर का भ्रमण किया गया। भ्रमण के समय वार्ड में भर्ती बच्चों सौर्य जैसवाल अजहरूल खान, प्रियापाल, सुष्मिता सिंह, सुशान्त, लाईवा, अरमान एवं अविनाश सिंह वार्ड से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा कि साथ ही निदेशक महोदय द्वारा बच्चों को गिफ्ट भी दिये गये तथा नोडल आफीसर द्वारा थैलेसीमिया प्रबन्धन हेतु डे केयर सेन्टर के बारे में जानकारी दी गयी। वार्ड में भर्ती अविनाश सिंह द्वारा बताया गया कि थैलेसीमिया पीडित होने के पश्चात भी जनपद गोरखपुर में 'फाइट अगेन्स्ट थैलेसीमिया संस्था' चलाने का कार्य किया जा रहा है। संस्था द्वारा नेपाल एवं निकटतम जनपदों के रोगिया को थैलेसीमिया रोकने एवं उचित प्रबन्धन पर कार्य किया जा रहा है। थैलेसीमिय पीडित बच्चे निदेशक महोदय को बताया कि इस सेन्टर पर बहुत अच्छी सुविधायें उपलब्ध हैं और अपनी खुशी भी जाहिर कि।

निदेशक महोदय बताया कि संस्थान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्तपोषित थैलेसीमिया डे केयर सेंटर जुलाई 2023 से क्रियान्वित है, जो कि प्रदेश का पहला केन्द्र है (थैलेसीमिया रोगी के लिए ओपीडी, आयरन चिलेशन एवं अन्य दवाओं के साथ बिना प्रतिस्थापित के निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराया जाता है) मरीजों को उनकी ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की तिथियों के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाता है ताकि वे बिना किसी प्रतिक्षा समय के साथ ब्लड ट्रान्सफ्यूजन की सुविधा प्राप्त कर सके। थैलेसीमिया सोसाइटी लखनऊ ने बच्चों के लिए एक प्ले रुम डे केयर सेन्टर में स्थापित किया है। हमारे केन्द्र द्वारा प्रदान की गई इन सुविधाओं के कारण आज तक ब्लड ट्रांस्फ्यूजन कराने वाले रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही रही है, थैलेसीमिया डे केयर सेंटर में 160 थैलेसीमिया रोगीयों को पंजीकृत किया जा चुका है और रोगी हर 15 से 30 दिनों में ब्लड ट्रांस्फ्यूजन कराते है। अब तक संस्थान के डे केयर सेन्टर में 916 युनिट ब्लड ट्रांस्फ्यूजन हो चुका है। निदेशक महोदय द्वारा रक्तकोष का भी भ्रमण कर स्वैच्छिक रक्त दान शिविर का उदघाटन किया गया।

ब्लड बैंक प्रभारी एवं नोडल आफिसर थैलेसीमिया डे केयर सेन्टर डा0 वी0के0 शर्मा ने बताया कि रक्तकोष में आटोमेटिक इम्यूनो हिमैटोलोजी एनालाइजर का संचालन आरंभ हो चुका है, जिससे रोगियों को ग्रुपिंग एवं क्रास मैचिंक करके उच्चगुणवत्ता का रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मशीन के द्वारा थैलेसीमिया, कैसर व अन्य रोगियों को का एन्टीबाडीस्क्रीनिंग एवं फिनो टाइपिंग करके रक्त एवं रक्त अवयव उपलब्ध कराया जा रहा है। रक्त कोष में ल्यूकोडिपिलिटेड रक्त एवं रक्त अवयव भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

लक्ष्य निर्धारण करने से मिलती है सफलता - रमेश चंद्र श्रीवास्तव

सैनिक स्कूल अमेठी में छः सौ दसवां रैंक पाने वाली छात्रा को प्रबंधक ने किया सम्मानित

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। कड़ी मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। सफलता उसी को मिलती है जो अपना लक्ष्य निर्धारण कर कठिन से कठिन परिश्रम करते रहते हैं।यह बातें मार्डन ग्रुप आफ एजूकेशन जाना के प्रबंधक रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने कक्षा आठ मे पढ़ने वाली मेधावी छात्रा स्वीजल कशौधन द्वारा सैनिक स्कूल अमेठी में कक्षा नौ प्रवेश परीक्षा में सम्मान जनक अंक लाने पर उसे सम्मानित करते हुये कहा।उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा चाहे वह चाहे शहर क्षेत्र का हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र का अगर उस बच्चे मे शिक्षा के रुचि है तो एक दिन वह बुलंदियों को छूते हुए सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने माता–पिता, स्कूल के प्रबंधक, शिक्षक व समाज के साथ साथ समाज व राष्ट्र का नाम रोशन करेगा।बताते चलें कि इस स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा आठ की छात्रा स्वीजल कशौधान ने सैनिक स्कूल अमेठी के कक्षा नौ की प्रवेश परीक्षा में चौवालीस लाख बच्चों में छः सौ दसवां रैंक लाकर अपने पिता सत्येंद्र कुमार कशौधन व माता प्रियंका कशौधन के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों व पढ़ने वाले बच्चों व उनके परिजनों के साथ साथ प्रधानाचार्य व शिक्षकों का है।इस मौके पर मेधावी छात्रा स्वीजल कशौधन को स्कूल के

क्षेत्र का का नाम रोशन किया है।इस मौके पर स्कूल के सहायक प्रबंधक आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि हमारा स्कूल निरंतर बुलंदियों को छू रहा है।जिसमें मुख्य योगदान यहां पर निदेशक रमेश चंद्र श्रीवास्तव, सहायक प्रबंधक आशीष श्रीवास्तव व प्रधानाचार्य कौशल किशोर सिंह सहित स्कूल के सभी शिक्षक, शिक्षिका व छात्र छात्राएं मौजूद रहे।

सेठ एमद्गआरद्गजयपुरिया स्कूल,गोयल कैम्पस के सभागार में यू0के0 जी0 के युवा विद्वानों का प्री–ग्रेजुएशन समारोह

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। सेठ एम० आर० जयपुरिया स्कूल के सभागार में ष्ज्वायफुल एडोबष्सोच का पालन

करने वाले छात्रों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोयल ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट्स चेयरमैन महेश गोयल,प्रधानाचार्या डॉ० रीना पाठक,उप प्रधानाचार्य (सीनियर वर्ग) सुशांत श्रीवास्तव,उप प्रधानाचार्या (जूनियर वर्ग) शिल्पी जैन तथा मुख्य अतिथिगण श्रद्धा ठाकुर, सबा आजाद,महाप्रबंधक आर. बी. आई,लखनऊ के करकमलों द्वारा दीप प्रज्जवलन से किया गया।, इस अवसर ग्लोबल क्लासरूम प्राइवेट लिमिटेड के प्रशिक्षकों और अभिभावकों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम का आयोजन दो पालियों में किया गया। प्रथम पाली में नर्सरी बी के छात्रों ने स्वागत गीत पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया।इसी श्रृंखला में नर्सरी बी के छात्रों ने संस्कृत में श्लोक वाचन किया नन्हे मुन्ने छात्रों के वाचन कौशल से सभागार में उपस्थित सभी आगंतुक भावविभोर हो गए। छात्रों ने कृष्ण, यशोदा ,राम जी का किरदार निभाते हुए अद्भुत झाँकी प्रस्तुत की। कृष्ण जी ने सभी आंगुतकों के साथ फूलों की होली खेलकर उन्हें उपहार स्वरूप बांसुरी प्रदान की।कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में नर्सरी ए के छात्रों ने बार्बी डांस की प्रस्तुति कर सभी का मन मोह लिया।कार्यक्रम में विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करते हुए छात्रों कई प्रदेशों की पोशाकें पहनकर नृत्य किया।कार्यक्रम की दूसरी पाली का आरंभ दोपहर 12 बजे से हुआ।जिसमें एल० के०जी० के छात्रों ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर सभी का स्वागत किया। तत्पश्चात् कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथियों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना उन्हें आर्शीवचन दिए। चेयरमैन महेश अग्रवाल और विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. रीना पाठक ने छात्रों के प्रयासों की सराहना की । उप प्रधानाचार्य सुशांत श्रीवास्तव और उप प्रधानाचार्या शिल्पी जैन ने सभी अभिभावकों और अतिथियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की।

लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा प्रोग्राम एलयूसीओडीई का किया शुभारम्भ

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। भारत में उच्च शिक्षा सर्वसुलभ हो, इस स्वप्न को वास्तविकता में परिणित करने हेतु तथा शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नवीन आयाम जोड़ने हेतु शताधिक वर्षीय लखनऊ विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन शिक्षा प्रोग्राम LUCODE का शुभारम्भ कर दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य विश्वविद्यालय है जो रेगुलर तथा ऑनलाइन शिक्षा प्रोग्राम दोनों ही ऑफर कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि NAAC A तथा कैटेगरी 1 विश्वविद्यालय है, को वदसपदम मकनबंजपवद हेतु दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

वर्ष 2023 – 24 के फरवरी 2024 से प्रारम्भ होने वाले सेमेस्टर में BCom तथा MCom online education program के प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया हो गई है। इन उपाधियों की मान्यता विश्वविद्यालय की रेगुलर उपाधियों के समकक्ष है। BCom उपाधि हेतु विद्यार्थियों को छः सेमेस्टर (तीन वर्ष) उत्तरीण करने होंगे। प्रत्येक सेमेस्टर में छः विषय होंगे जिनका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के रेगुलर बीकॉम जैसा ही है। विद्यार्थियों को सभी व्याख्यान का पीडीएफ तथा वीडियो ऑनलाइन ही उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी समस्यायों और प्रश्नों का समाधान भी शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन ही किया जाएगा। एसाइनमेंट भी ऑनलाइन होगा। छः माह में मात्र सेमेस्टर परीक्षा हेतु ही विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय आना होगा, जो कि प्रत्यक्ष लिखित माध्यम से संपन्न होगी। बी कॉम की रजिस्ट्रेशन फीस रू250/ तथा शिक्षा शुल्क रू5000/ प्रति सेमेस्टर है । इसी प्रकार MCom हेतु चार सेमेस्टर (दो वर्ष) उत्तरीण करने होंगे तथा फीस रू8000/ प्रति सेमेस्टर है। रजिस्ट्रेशन फीस रू 250 ही है। इन प्रोग्रामों में प्रवेश हेतु सम्पूर्ण भारत देश के सभी नागरिक आवेदन कर सकेंगे तथा अधिकतम आयु सीमा नहीं रहेगी। जो छात्र किसी कारणवश रेगुलर रूप से विश्विद्यालय नहीं आ सकते, उनके लिए यह प्रोग्राम एक वरदान स्वरूप है। आगामी वर्ष में विश्वविद्यालय अन्य पाठ्यक्रम जैसे अंग्रेजी, संस्कृत, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर

तथा अन्य स्नातक प्रोग्राम भी आरम्भ करेगा। दोनों कक्षाओं हेतु Registration करने तथा प्रवेश फॉर्म भरने की अन्तिम तिथि मार्च 31, 2024 है। यू जी सी के नियमानुसार इस तिथि के उपरान्त प्रवेश बन्द कर दिए जायेंगे।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक **देश की उपासना**

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI सन्दर्भ संख्या - 24/234/2019/R/-1
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।